दृष्टि The Vision

Prelims Practice Series

प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़

(6 पुस्तकों की शृंखला की चौथी कड़ी)

भारतीय अर्थव्यवस्था

विभिन्न परीक्षाओं जैसे IAS, PCS, CDS, NDA, CAPF, UGC-NTA NET में अभी तक पूछे गए या पूछे जा सकने वाले 1200+ प्रश्नों व उनकी व्याख्याओं का संकलन

1200+ अभ्यास प्रश्न (व्याख्या सहित)

दृष्टि The Vision | drishti

Think IAS Think Drishti

अब घर बैठे कीजिये आई.ए.एस. की तैयारी क्योंकि हम आ रहे हैं आपके घर

आई.ए.एस. प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स
(IAS Prelims Online Course)

प्रिय विद्यार्थियो,

संसाधन की कमी अक्सर हमारी उड़ान को सीमित कर देती है। हममें आगे बढ़ने की तड़प तो खूब होती है किंतु उसे साकार करने वाले साधनों का अभाव हमें मायूस कर देता है। पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न हिस्सों से आप जैसे हज़ारों विद्यार्थियों ने हमें इस आशय के संदेश भेजे कि वो सिविल सेवा में जाने की इच्छा तो रखते हैं किंतु इसकी तैयारी के लिये दिल्ली में रहने का भारी-भरकम खर्च उठा पाना उनके लिये संभव नहीं है। साथ ही आपने हमसे यह अपेक्षा भी व्यक्त की कि हम ऐसी कोई व्यवस्था करें जिसमें आप घर-बैठे दृष्टि की कक्षा कार्यक्रम जैसी गुणवत्तापरक क्लास कर पाएँ। आपके इन्हीं निवेदनों को ध्यान में रखते हुए हम अपना पहला 'पेन ड्राइव कोर्स' जारी कर रहे हैं जो आई.ए.एस. प्रिलिम्स के पाठ्यक्रम पर केंद्रित है। इसमें आप सामान्य अध्ययन तथा सीसैट के कोर्स ले सकते हैं। लगभग 2 वर्षों की कठोर मेहनत से तैयार हुआ यह वीडियो कोर्स गुणवत्ता में अच्छे से अच्छे क्लासरूम प्रोग्राम को टक्कर दे सकता है। हमें विश्वास है कि यह कोर्स उस अंतराल को भरने में सफल होगा जो दिल्ली में रहकर तैयारी करने वाले और दिल्ली नहीं आ पाने वाले विद्यार्थियों के बीच बना रहता है। निकट भविष्य में हम IAS मुख्य परीक्षा और विभिन्न राज्यों की PCS परीक्षाओं के लिये भी ऑनलाइन कोर्स शुरू करेंगे।

एडमिशन प्रारंभ

विद्यार्थियों की भारी माँग को देखते हुए ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्स पर 20% की विशेष छूट अब शुरुआती 1000 विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध

मोड : पेन ड्राइव

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS की प्लेलिस्ट Online Courses में देखें

ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट www.drishtiias.com पर FAQs पेज देखें

IAS प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

1. 500+ घंटे की सामान्य अध्ययन की कक्षाएँ।
2. 120+ घंटे की सीसैट की कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा ताकि आप रिवीज़न भी कर सकें।
4. कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल। इमेज, वीडियो आदि की मदद से कठिन विषय समझाने की शैली।
5. हर क्लास के अंत में उस टॉपिक से IAS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का अभ्यास।
6. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
7. प्रिलिम्स के ठीक पहले करेंट अफेयर्स की 30 ऑनलाइन कक्षाएँ (निशुल्क)।
8. ऑनलाइन प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ (25+5 टेस्ट) की निशुल्क सुविधा।
9. क्विक बुक सीरीज़ की 8 पुस्तकें निशुल्क, जिनके अलावा कोई और स्टडी मैटीरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं।
10. इस कोर्स को करने के बाद अगर आप दृष्टि की किसी भी शाखा में सामान्य अध्ययन (फाउंडेशन कोर्स) करते हैं तो आपकी ऑनलाइन कोर्स की फीस की 50% राशि की छूट दी जाएगी।

जानकारी के लिये कॉल करें- 9319290700, 9319290701, 9319290702 या सिर्फ मिस्ड कॉल करें- 8010600300

दिल्ली शाखा का पता : 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09

प्रयागराज शाखा का पता : ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइंस, प्रयागराज

Ph.: 8448485517, 8448485519, 87501 87501, 011-47532596

प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़

भारतीय अर्थव्यवस्था

विभिन्न परीक्षाओं जैसे IAS, PCS, CDS, NDA, CAPF, UGC-NTA NET में अभी तक पूछे गए या पूछे जा सकने वाले 1200+ प्रश्नों व उनकी व्याख्याओं का संकलन

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501

Website: www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com

E-mail : booksteam@groupdrishti.com

प्रथम संस्करण- जून 2020

मूल्य : ₹ 240

प्रकाशक

दृष्टि पब्लिकेशन्स,
(A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.)
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

✸ इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।

✸ हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है, तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

✸ सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।

✸ **© कॉपीराइट:** दृष्टि पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

✸ एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द

प्रिय पाठको,

युवाल नोआ हरारी अपनी लोकप्रिय पुस्तक 'सेपियंस' में ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी की शुरुआत में तीन ऐसी व्यवस्थाओं के उदय की बात करते हैं जो एकता की सूत्र पर आधारित थीं तथा समस्त मानव जाति को लक्षित करके परिकल्पित की गई थीं। उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण व्यवस्था थी 'वित्तीय व्यवस्था'। यह एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था विकसित करने की कोशिश थी, जो हर कहीं व हर किसी पर लागू होती हो। धातुओं की मुद्रा आधारित आर्थिक प्रणाली से आज डिजिटल मुद्रा तक के विकास में एक बात जो समान रही है, वह यह कि हर व्यक्ति का इस मुद्रा पर भरोसा होना। हरारी के ही शब्दों में कहें तो "जो लोग समान देवता में विश्वास नहीं करते या समान राजा का आदेश नहीं मानते, वे भी समान पैसे का इस्तेमाल करने को तत्पर होते हैं। ओसामा बिन लादेन अमेरिकी संस्कृति, अमेरिकी धर्म और अमेरिकी राजनीति के प्रति अपनी सारी नफरत के बावजूद अमेरिकी डॉलर्स से बहुत प्रेम करता था। जहाँ देवता और सम्राट नाकामयाब रहे वहाँ पैसे ने कामयाबी हासिल कर ली।"

उपर्युक्त प्रसंग से आपको यह तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि किस प्रकार आर्थिक गतिविधियाँ विश्व व्यवस्था के संचालन के केंद्र में आ गई हैं। आज तो यह और इतनी जटिल हो गई हैं कि राजनीतिक दुश्मनी भी आर्थिक हितों को प्रभावित नहीं कर पा रही है। भारत और चीन के उदाहरण को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। आपस में युद्ध लड़ चुके इन दोनों देशों के बीच लगातार सीमा पर तनाव बना रहता है पर साथ-ही-साथ सीमापारीय व्यापार भी चलता रहता है। आर्थिक संपन्नता आज इतनी ही ज़रूरी हो गई है। तो ऐसे में यह आवश्यक ही है कि नीति-निर्माण में भी यह आर्थिक पक्ष महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिये देश की सर्वोच्च सेवा के चुनाव में भी यह बात काफी मायने रखती है कि अभ्यर्थियों को अर्थव्यवस्था की कितनी समझ है।

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि अर्थव्यवस्था से निर्णायक प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं कर सकता कि वह इस खंड के प्रति लापरवाही बरते और परीक्षा पास कर जाए, बल्कि यह एक ऐसा खंड है जिसपर सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि औसतन बीस प्रश्न इस खंड से हर वर्ष पूछे ही जाते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसके लिये आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होने की अनिवार्यता नहीं है बल्कि उन मूलभूत सिद्धांतों और उनके अनुप्रयोगों से परिचय ही पर्याप्त है जिनसे अर्थव्यवस्था संचालित होती है। आपने अक्सर यह भी सुना होगा कि जब अर्थव्यवस्था के अधिकांश प्रश्न समसामयिक घटनाओं पर ही आधारित होते हैं, तो फिर परंपरागत अवधारणाओं को पढ़ने में इतना समय क्यों निवेश किया जाए? यह धारणा अधकचरी समझ को दर्शाती है और अगर आप इसका पालन करेंगे तो आपको निर्णायक नुकसान होना तय है। मूल बात यह है कि अगर आपको बुनियादी धारणाओं की समझ ही नहीं है, तो आप उसमें आए परिवर्तनों को कैसे समझ सकेंगे? उदाहरण के लिये, यदि आपने बैंकिंग व्यवस्था को ठीक से नहीं पढ़ा है तो फिर आप रेपो रेट में हुए परिवर्तन से आर्थिक जगत पर पड़ने वाले प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। इससे रेपो रेट के बारे में आपको बस एक अतिरिक्त तथ्य पता चलेगा, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था संबंधी समझ में कोई विस्तार नहीं होगा। इसलिये आवश्यक है कि पहले बुनियादी बातों को जान लिया जाए ताकि नवीन परिवर्तनों की समीक्षा करना आसान हो जाए। फिर सिविल सेवा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखें, तो लगभग हर प्रश्न ऐसा होता है जिसका संदर्भ समसामयिक ज़रूर होता है किंतु उसमें अनिवार्य रूप से आधारभूत ज्ञान की जाँच शामिल होती है। अत: बेहतर रणनीति यही है कि इसी अनुरूप तैयारी की जाए।

प्रस्तुत पुस्तक 'प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़' की ही अगली कड़ी है। इसमें अर्थव्यवस्था के संपूर्ण पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है, साथ ही उन अध्यायों पर विशेष फोकस किया गया है जिनकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की अधिक संभावना है। प्रश्नोत्तर आधारित इस पुस्तक को आद्योपांत पढ़ने का एक लाभ यह होगा कि आप अपने मज़बूत और कमज़ोर पक्ष को जान पाएंगे तथा उसी अनुरूप अपनी रणनीति तैयार कर सकेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है यह टॉपिक तो पूरी तरह समझ में आ गया किंतु उससे संबंधित प्रश्न हल नहीं हो पाते। परीक्षा भवन में ऐसी स्थिति न आए इसलिये बेहतर है कि पहले ही इसे जाँच लिया जाए कि किन-किन टॉपिक्स के साथ ऐसी दिक्कत आ रही है। फिर व्याख्या के माध्यम से आप उसे पुन: समझ भी सकते हैं, जिससे सिलेबस भी रिवाइज़ हो जाएगा। हमने इस पुस्तक में पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया है ताकि आपको यह अनुमान रहे कि इन प्रश्नों की कठिनाई का स्तर क्या होगा। इस प्रकार हमने लगभग 1200 प्रश्न व उनकी व्याख्या को इस पुस्तक में शामिल किया है। हमें पूरा विश्वास है कि यह पुस्तक आपकी तैयारी में सहायक होगी।

अंत में यही कि इस पुस्तक को आप एक पाठक के साथ-साथ आलोचक की नज़र से भी पढ़ें। कोई गलती दिखे तो हमें बताएँ, हम उसे यथाशीघ्र ठीक करेंगे। आपको लगे कि इस पुस्तक ने आपकी तैयारी में महती भूमिका निभाई है तो हमें बताएँ, हमारा उत्साह बढ़ेगा। आप अपनी बात हमें '8130392355' नंबर पर वाट्सएप मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं।

साभार,
प्रधान संपादक
दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

1. अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था : एक नज़र में 1-22

2. राष्ट्रीय आय 23-33

3. आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास 34-45

4. भारत में भूमि सुधार 46-50

5. कृषि क्षेत्र 51-65

6. औद्योगिक क्षेत्र 66-91

7. आर्थिक नियोजन 92-100

8. नीति आयोग 101-103

9. गरीबी 104-109

10. बेरोज़गारी 110-115

11. खाद्य सुरक्षा 116-122

12. मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र 123-134

13. मुद्रा बाज़ार एवं बैंकिंग प्रणाली 135-166

14. भारत में बीमा और पूंजी बाज़ार 167-180

15. राजकोषीय नीति एवं कर संरचना 181-203

16. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): क्यों, क्या और कैसे? 204-207

17. निवेश मॉडल 208-211

18. भारत का वैदेशिक क्षेत्र 212-238

19. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, समूह एवं समझौते 239-266

20. जनसांख्यिकीय सिद्धांत और जनगणना 267-278

21. विविध 279-284

1 अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था : एक नज़र में (Economics And Economy : At A Glance)

1. समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन-किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है?
   1. राजकोषीय नीति
   2. मौद्रिक नीति
   3. मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति
   4. सरकारी बजट

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 4
   (c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)
व्याख्या: समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के वृहद स्तर के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य विषय/घटक हैं-
- राजकोषीय नीति
- मौद्रिक नीति
- मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति
- सरकारी बजट
- भुगतान संतुलन
- विनिमय दर
- मुद्रा आपूर्ति एवं साख सृजन
- रोज़गार इत्यादि।

अत: विकल्प (d) सही है।

2. कोई बाज़ार, जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में हैं, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते-जुलते उत्पाद बेचता है, क्या कहलाता है?
   (a) पूर्ण स्पर्धा (b) एकाधिपत्य
   (c) एकाधिकारी स्पर्धा (d) अल्पाधिकार

उत्तर: (c)
व्याख्या: बाज़ार में जब वस्तु या सेवा का केवल एक ही विक्रेता हो, जो उसके विक्रय से संबंधित शर्तों एवं मूल्यों को अपनी इच्छानुसार लागू कर सके तो यह स्थिति एकाधिपत्य या एकाधिकार कहलाती है।
- पूर्ण स्पर्धा बाज़ार का वह रूप है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। परिणामस्वरूप कोई भी एक विक्रेता अथवा क्रेता बाज़ार में विक्रय से संबंधित कीमतों पर प्रभाव नहीं डाल सकता।
- अल्पाधिकार वह स्थिति है जिसमें विक्रेताओं की संख्या कम किंतु क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। ऐसे बाज़ार में प्रतिस्पर्धा विद्यमान होती है। अत: विकल्प (c) सही है।

3. निम्नलिखित में से कौन-सा/से सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का/के आधार बनता/बनते है/हैं?
   1. निरपेक्ष लागत अंतर
   2. तुलनात्मक लागत अंतर
   3. अवसर लागत

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)
व्याख्या: निरपेक्ष लागत अंतर का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। उनके अनुसार दो देशों में व्यापार उस स्थिति में होता है यदि उनमें से एक को वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है तथा दूसरे देश को दूसरी वस्तु के उत्पादन में लाभ है।
- रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है अर्थात् किसी वस्तु का मूल्य उसके श्रम लागत पर निर्भर करता है। अवसर लागत सिद्धांत के प्रतिपादक हैबलर थे। अवसर लागत से आशय एक वस्तु की दूसरी वस्तु से प्रतिस्थापन करने की लागत से है। अत: विकल्प (d) सही है।

4. सभी आगतों में एक ही अनुपात में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल उत्पाद में जिस तरह परिवर्तन होता है, उसे कौन-से नियम के रूप में जानते हैं?
   (a) पैमाने का प्रतिफल (b) ह्रासमान प्रतिफल
   (c) वर्धमान प्रतिफल (d) स्थिर प्रतिफल

उत्तर: (a)
व्याख्या: सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि, निर्गत में उसी अनुपात में वृद्धि उत्पन्न करती है तो उत्पादन फलन पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है तथा जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि, निर्गत में अनुपात से अधिक वृद्धि उत्पन्न करती है, तो उत्पादन फलन पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल को प्रदर्शित करता है। वहीं जब सभी आगतों के आनुपातिक वृद्धि की तुलना में, निर्गत में समानुपातिक वृद्धि कम होती है तो यह ह्रासमान प्रतिफल को दर्शाता है। अत: विकल्प (a) सही है।

5. वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करती है?
   (a) उस वस्तु की इच्छा
   (b) उस वस्तु की आवश्यकता
   (c) उस वस्तु का मांगा गया परिमाण
   (d) किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिमाण

उत्तर: (d)
व्याख्या: एक निश्चित कीमत पर, एक विशिष्ट समयावधि के भीतर खरीदी जाने वाली वस्तु का परिमाण ही मांग है। ध्यातव्य है कि किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के बीच के संबंध को मांग का नियम कहते हैं। अत: विकल्प (d) सही है।

2

राष्ट्रीय आय
(National Income)

1. एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्यक्षेत्र के भीतर परिचालित हों या बाहर, क्या कहते हैं?
   (a) सकल राष्ट्रीय आय GNI (b) निवल राष्ट्रीय आय NNI
   (c) सकल घरेलू उत्पाद GDP (d) निवल घरेलू उत्पाद NDP

उत्तर: (a)
व्याख्या: सकल राष्ट्रीय आय (GNI), किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल निवासी उत्पादक इकाइयों अर्थात् देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। वहीं निवल राष्ट्रीय आय (NNI) की प्राप्ति हेतु देश के निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़कर, विदेशी नागरिकों द्वारा देश में अर्जित आय को घटाया जाता है। इस अंतिम आय से मूल्य ह्रास की राशि को निकाल दिया जाता है। अत: विकल्प (a) सही है।

2. राष्ट्रीय आय (NI) लेखे में निजी आय (PI) को किस रूप में परिभाषित किया गया है?
   (a) राष्ट्रीय आय – अवितरित लाभ – परिवारों द्वारा किया गया नेट ब्याज़ भुगतान – कंपनी कर + सरकार और फर्मों द्वारा परिवारों को अंतरण भुगतान
   (b) राष्ट्रीय आय – अवितरित लाभ – कंपनी कर + सरकार और फर्मों द्वारा परिवारों को अंतरण भुगतान
   (c) अवितरित लाभ – परिवारों द्वारा किया गया नेट ब्याज़ भुगतान + सरकार और फर्मों द्वारा परिवारों को अंतरण भुगतान
   (d) अवितरित लाभ – परिवारों द्वारा किया नेट ब्याज़ भुगतान – कंपनी कर

उत्तर: (a)
व्याख्या: राष्ट्रीय आय जो फर्मों और सरकारी उद्यमों द्वारा अर्जित की जाती है; में से लाभ का एक अंश उत्पादन के कारकों के बीच वितरित नहीं होता है, इसे अवितरित लाभ कहते हैं। चूँकि अवितरित लाभ तथा फर्मों की आय पर आरोपित निगम कर परिवारों को उपार्जित नहीं होता इसलिये निजी आय की प्राप्ति के लिये राष्ट्रीय आय से अविरित लाभ और निगम कर घटा दिये जाते हैं। दूसरी ओर परिवार निजी फर्मों अथवा सरकार से अपने अग्रिम पूर्व ऋण पर ब्याज़ अदायगी प्राप्त करता है। यदि परिवार फर्म और सरकार से मुद्रा ऋण के रूप में ग्रहण करते हैं तब परिवार को इन्हें भी ब्याज़ अदा करना पड़ता है। इस प्रकार निजी आय की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय आय से परिवारों द्वारा किया गया नेट ब्याज़ भुगतान घटाना होता है। अर्थात् निजी आय = राष्ट्रीय आय – अवितिरित लाभ – परिवारों को किया गया नेट ब्याज़ भुगतान – कंपनी कर + सरकार और फर्मों द्वारा परिवारों को अंतरण भुगतान। अत: विकल्प (a) सही है।

3. निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊँची दर का संकेत *नहीं* करतीं, यदि
   (a) औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है।
   (b) कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है।
   (c) निर्धनता और बेरोज़गारी में वृद्धि होती है।
   (d) निर्यातों की अपेक्षा आयात तेज़ी से बढ़ते हैं।

उत्तर: (c)
व्याख्या: आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था के गुणात्मक पक्षों से संबंधित होता है। यह समाज के वंचित वर्गों के हितों का भी संवर्द्धन करता है। इस प्रकार, यदि प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP वृद्धि के बावजूद निर्धनता व बेरोज़गारी में वृद्धि हो रही हो, तो इसे आर्थिक विकास का पर्याय नहीं माना जाएगा। अत: विकल्प (c) सही है।

4. किसी भी राष्ट्र की औसत आय/प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जा सकती है?
   (a) जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय ₹1 लाख है, उनकी कुल आय को कुल जनसंख्या से गुणा करके।
   (b) देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर।
   (c) सरकार द्वारा प्राप्त कुल कर की राशि को कुल जनसंख्या से भाग देकर।
   (d) गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर।

उत्तर: (b)
व्याख्या: किसी भी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिये कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। क्योंकि हर देश की जनसंख्या अलग-अलग होती है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? वस्तुत: इसके लिये हम औसत आय की तुलना करते हैं। औसत आय देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रतिव्यक्ति आय भी कहा जाता है।

5. स्वतंत्रता से पूर्व भारत की 'राष्ट्रीय तथा प्रतिव्यक्ति आय' के आकलनकर्त्ताओं में निम्नलिखित में से कौन-कौन शामिल थे?
   1. दादाभाई नौरोजी 2. फिडले शिराज़
   3. डॉ. वी.के.आर.वी. राव 4. आर.सी. देसाई

   कूट:
   (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

3 आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास (Economic Growth and Economic Development)

1. UNO द्वारा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (MDGs), 2015 के स्थान पर अपनाए गए धारणीय विकास लक्ष्य (SDGs) का उद्देश्य, किस वर्ष तक 17 लक्ष्य प्राप्त करना है?
   (a) 2020 (b) 2030
   (c) 2040 (d) 2050

उत्तर: (b)

व्याख्या: 17 धारणीय विकास लक्ष्य (SDGs) और 169 उद्देश्य, सतत अथवा धारणीय विकास के लिये 2030 एजेंडा के अंग हैं जिसे सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था। यह एजेंडा जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ है। इस प्रकार वर्ष 2030 तक 17 धारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अत: विकल्प (b) सही है।

2. भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिये संसाधनों को बढ़ाने के लिये उपयोग की जाती है?
   (a) आर्थिक विकास के लिये
   (b) सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिये
   (c) भुगतान शेष का समायोजन करने के लिये
   (d) विदेशी ऋण कम करने के लिये

उत्तर: (a)

व्याख्या: जब घरेलू संसाधन तथा बाह्य सहायता सम्मिलित रूप से भी विकासात्मक खर्च की पूर्ति में अपर्याप्त सिद्ध हो जाते हैं, तब वहाँ की सरकार घाटे के वित्तीय पोषण के लिये बाध्य होती है। यह स्थिति सामान्यत: विकासशील अथवा अल्प विकसित देशों में आती है जहाँ आय का स्तर तो निम्न होता है किंतु उपभोग की प्रवृत्ति उच्च होती है, परिणामत: बचत काफी कम हो जाती है। इस दशा में सरकार का दायित्व बनता है कि विकास कार्यों को सहज बनाए रखने के लिये संसाधनों का संवर्द्धन करे। यह अतिरिक्त राशि की मांग करती है जिसकी पूर्ति निम्नांकित तरीकों से की जाती है-

- केंद्रीय बैंक से उधार
- वाणिज्यिक बैंकों से उधार
- नई मुद्रा का सृजन

अत: विकल्प (a) सही है।

3. आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है-
   (a) अवस्फीति के साथ
   (b) स्फीति के साथ
   (c) स्टैगफ्लेशन के साथ
   (d) अतिस्फीति के साथ

उत्तर: (b)

व्याख्या: आर्थिक विकास सामान्यतया पूंजी निर्माण, बचत, निवेश, मांग और आपूर्ति शृंखला में संतुलन, आयात-निर्यात आदि कारकों से संचालित होता है। संवृद्धि के लिये समस्त आर्थिक गतिविधियाँ बाज़ार में संपन्न की जाती हैं और वो भी मुद्रा के साथ। बाज़ार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि लेकिन आपूर्ति में कमी की स्थिति व कुछ अन्य कारक, वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर महँगाई की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। इस रूप में मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है।

4. x देश में आर्थिक संवृद्धि अनिवार्य रूप से होगी, यदि
   (a) विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है।
   (b) x में जनसंख्या वृद्धि होती है।
   (c) x में पूंजी निर्माण होता है।
   (d) विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है।

उत्तर: (c)

व्याख्या: विकल्प (c) सही है, क्योंकि पूंजी आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारकों में सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है। यह अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के स्तर, उत्पादन का ढाँचा, तकनीकी प्रगति, उत्पादन क्षमता आदि का निर्धारण करती है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि लाई जाती है, उसे हम पूंजी निर्माण कहते हैं। पूंजी निर्माण से संबंधित महत्त्वपूर्ण पहलू निम्नवत् हैं-

- पूंजी निर्माण से ही निवेश (Investment) को गति मिलती है। बिना पूंजी निर्माण के कोई राष्ट्र विश्व अर्थव्यवस्था में आई तकनीकी प्रगति का लाभ नहीं उठा सकता। केवल तकनीकी प्रगति से आर्थिक संवृद्धि होना अनिवार्य नहीं है।
- विकल्प (b) गलत है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि नहीं बल्कि जनांकिकीय लाभांश अथवा देश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कौशल विकास से आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित हो सकती है।
- विकल्प (d) सही नहीं है, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ जाने पर भी x देश में आर्थिक संवृद्धि तब तक नहीं होगी जब तक कि पर्याप्त मात्रा में पूंजी सुलभता आयात-निर्यात के लिये न हो। इस प्रकार पूंजी निर्माण से x देश में आर्थिक संवृद्धि अनिवार्य रूप से होगी।

5. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 'वित्तीय उत्प्रेरक' की समुचित व्याख्या करता है?
   (a) यह सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र में किया गया वृहद् निवेश है, जिसका लक्ष्य माल की आपूर्ति की तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करना है।

4 भारत में भूमि सुधार (Land Reforms in India)

1. स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
   (a) हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर।
   (b) भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था।
   (c) इसके परिणामस्वरूप नकदी फसलों की खेती, कृषि का प्रमुख रूप बन गई।
   (d) भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी।

उत्तर: (b)

व्याख्या: स्वतंत्रता उपरांत भारत में कृषि के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया। इसमें काश्तकारी कानून को अधिनियमित करने व ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करने से भूमिहीन किसानों को भी भूमि प्राप्त हो सकी, जिससे वे अपनी आजीविका चलाने में सक्षम हुए।

नोट: भूमि राज्य सूची का विषय है।

2. भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में, कौन-सा कथन सही है/हैं?
   1. लगान का विनियमन
   2. अवधि की सुरक्षा
   3. पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा

   नीचे दिये हुए कूट से सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में तीनों कथन सही हैं।

- पट्टेदारी या काश्तकारी (Tenancy) के अंतर्गत भूमि का मालिक खुद खेती नहीं करता और भूमि को काश्तकारों को कृषि कार्यों हेतु पट्टे पर दे देता है। स्वतंत्रता से पहले भारत में ज़मींदारी तथा रैयतवाड़ी दोनों ही प्रणालियों में भूमि को पट्टे पर देने की प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी। परंतु वर्तमान में पट्टेदारी या भूमि सुधार हेतु विभिन्न कदम उठाए गए हैं, अत: मध्यस्थों के उन्मूलन और काश्तकारी सुधारों से संबंधित सरकारी प्रयासों के आलोक में प्रमुख तीन नीतियों की चर्चा की जाती है।
- काश्त का अधिकार अस्थायी होने पर किसान की भूमि में वैयक्तिक रुचि कम होती है, परिणामस्वरूप वह खेत के रख-रखाव तथा विकास पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देता।
- पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा: विभिन्न योजनाओं में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि काश्तकार जिस भूमि पर खेती करते हैं, उन्हें उस पर स्वामित्व अधिकार प्रदान किये जाए अर्थात् उस भूमि का उसे मालिक बना दिया जाए।

3. भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था।
   2. भूमि सुधारों के अंतर्गत हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या: भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य भूमिहीन किसानों एवं काश्तकारों को भूमि वितरण करके सामाजिक एवं आर्थिक समानता सुनिश्चित करना था, जिससे ग्रामीण गरीबी व बेरोज़गारी की समस्या को हल किया जा सके। इसके साथ ही इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण अर्थात् आर्थिक न्याय के सिद्धांत को सुनिश्चित करना था। अत: कथन 1 सही है।

- हदबंदी से संबंधित कानून के अंतर्गत जोतों की उच्चतम सीमा बहुत ऊँची रखी गई और सीमा निर्धारण के लिये परिवार को इकाई न मानकर व्यक्ति को इकाई मान लिया गया। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- अत: विकल्प (a) सही है।

4. स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. वर्ष 1950 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया।
   2. 9वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य राज्यों द्वारा बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में शामिल करना था।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या: वर्ष 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। अत: कथन 1 सही नहीं है।

5 कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector)

1. भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. 'जैविक उत्पादन के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम' (एन.पी.ओ.पी.) केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निदेश के अधीन कार्य करता है।
   2. एन.पी.ओ.पी. के क्रियान्वयन के लिये 'कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण' (APEDA) सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
   3. सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या: जैविक कृषि (ऑर्गेनिक फार्मिंग), कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिये फसल चक्र, हरी खाद, कम्पोस्ट आदि का प्रयोग करती है। सन् 1990 के बाद से विश्व में जैविक उत्पादों का बाज़ार वर्तमान में काफी बढ़ गया है। प्रश्न में दिया गया कथन-1 सही नहीं है क्योंकि जैविक उत्पादन के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी.) केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य नहीं करता है बल्कि यह वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जैविक कृषि के केंद्रीय व सुव्यवस्थित विकास हेतु भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सन् 2001 में अपने उपक्रम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिये एन.पी.ओ.पी. (NPOP) की शुरुआत की गई। इस प्रमाणीकरण व्यवस्था के तहत एन.पी.ओ.पी. द्वारा सफल प्रसंस्करण इकाइयों, भंडारों और खेतों को इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो प्रदान कराया जाता है। वर्ष 2016 में सिक्किम देश का पहला पूर्णत: जैविक राज्य बन गया है। अत: प्रश्न में दिये गए कथन 2 एवं 3 सही हैं।

2. भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की 'बीज प्रतिस्थापन दरों' को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े/विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता है/बाध्यताएँ हैं?
   1. कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है।
   2. निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की, उद्यान-कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्ज़ियों के गुणता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है।
   3. निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणता वाले बीजों के बारे में मांग-पूर्ति अंतराल है।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) 1 और 2 (b) केवल 3
   (c) 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: राष्ट्रीय बीज नीति, 2002 स्पष्ट रूप से बीजों के उत्पादन के बारे में मानकों का निर्धारण करती है। अत: कथन (1) गलत है।

- राष्ट्रीय बीज नीति, 2002 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन व आपूर्ति में निजी क्षेत्र के बीज उद्योग अथवा बीज कंपनियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसी के अनुरूप निजी क्षेत्र की बीज कंपनियाँ आज उच्च मूल्य और निम्न परिमाण (High Value and Low Volume) वाली फसलों, जैसे- सब्ज़ियाँ, फूल, उद्यान कृषि फसल (Horticulture Crops), कुछ अनाजों तथा नकदी फसलों के हाइब्रिड और आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलों के मामले में बीजों की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण रूप से सहभागिता कर नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही हैं। अत: कथन 2 गलत है।
- कथन 3 सही है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणता वाले बीजों के विकास, उत्पादन और वितरण प्रणाली में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। भारत में निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणता वाले बीजों के बारे में मांग-पूर्ति अंतराल है। प्रमाणित (Certified) व गुणता वाले बीजों (Quality seeds) के मांग-आपूर्ति अंतराल के चलते भारत में बीज प्रतिस्थापन दर निम्न बनी हुई है। निम्न मूल्य व उच्च परिमाण वाली फसलों, जैसे- चावल व गेहूँ के मामले में भारत में प्रमाणित व गुणता वाले बीजों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाई है। फलों, सब्ज़ियों व फूलों के संदर्भ में ऐसा नहीं है।

3. भारत में कृषि उत्पादों के बाज़ार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है?
   (a) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
   (b) राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम
   (c) कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम, 1937
   (d) खाद्य उत्पाद आदेश, 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश, 1973

उत्तर: (b)

व्याख्या: भारत में कृषि उत्पादों के बाज़ार को राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम (APMC Act) के अधीन विनियमित किया जाता है। अत: विकल्प (b) सही है। एपीएमसी कानून के तहत कृषि को राज्य सूची के प्रमुख मुद्दे के रूप में अपनाया गया है। यह एक्ट राज्य सरकारों को वस्तुओं को अधिसूचित करने हेतु सशक्त करता है एवं APMC बाज़ारों (मंडियों) के गठन का अधिकार देता है।

6 औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Sector)

1. 2017 में लागू नीति के अनुसार, भारत में रक्षा क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है?
   (a) स्वचालित मार्ग के ज़रिये 49 प्रतिशत
   (b) सरकारी मार्ग के ज़रिये 26 प्रतिशत
   (c) स्वचालित मार्ग के ज़रिये 26 प्रतिशत और उसके परे (ऊपर) सरकारी मार्ग के ज़रिये 49 प्रतिशत तक
   (d) स्वचालित मार्ग के ज़रिये 75 प्रतिशत

उत्तर: (a)
व्याख्या: 2017 में लागू नीति के अनुसार, भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के ज़रिये 49% एवं सरकारी मार्ग के ज़रिये 100% तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। अत: विकल्प (a) सही है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, 'अभिहित पूंजी' का क्या निहितार्थ है?
   (a) पूंजी का वह हिस्सा, जो संदाय के लिये मांग लिया गया है
   (b) किसी कंपनी की शेयर पूंजी की अधिकतम रकम
   (c) पूंजी का वह हिस्सा, जो कंपनी ने अपने शेयरधारकों से प्राप्त किया है
   (d) वह पूंजी, जो कंपनी समय-समय पर अभिदान के लिये जारी करती है

उत्तर: (b)
व्याख्या: अभिहित पूंजी या 'अधिकृत पूंजी' से आशय है कि एक कंपनी अपने जीवन काल में इससे अधिक पूंजी जारी नहीं कर सकती है। इसे नाममात्र पूंजी भी कहा जाता है। यह किसी कंपनी के शेयर पूंजी की अधिकतम रकम होती है। अत: विकल्प (b) सही है।

3. निजीकरण में समाहित है-
   (a) सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्र को बेचना
   (b) सार्वजनिक उद्यम इक्विटी का विनिवेश
   (c) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन में निजी क्षेत्र की सहभागिता
   (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)
व्याख्या: निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है, जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का स्वामी बन जाता है अथवा उसका प्रबंधन करता है। व्यापक रूप से निजीकरण का अभिप्राय निजी स्वामित्व के अतिरिक्त (अर्थात् स्वामित्व में परिवर्तन किये बिना भी) सार्वजनिक उद्योगों में निजी प्रबंधन एवं नियंत्रण के प्रवेश से लगाया जाता है। अत: विकल्प (d) सही है।

4. स्टार्टअप इंडिया हब (केंद्र) को उद्यमियों के प्रश्नों का समाधान करने और स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन देने (हैंडहोल्ड) के लिये कब क्रियाशील किया गया था?
   (a) 2015 (b) 2016
   (c) 2017 (d) 2018

उत्तर: (b)
व्याख्या: स्टार्टअप इंडिया हब 1 अप्रैल, 2016 को उद्यमियों के प्रश्नों का समाधान करने और स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन देने के लिये क्रियाशील किया गया तथा 16 जनवरी, 2017 को पोर्टल के विकास की घोषणा की गई। स्टार्टअप के लिये वर्चुअल हब (Virtual Hub) एक गत्यात्मक मंच है जो उद्यमियों के शिक्षण एवं विकास, नेटवर्किंग, संरक्षण, वित्त पोषण आदि को सुगम बनाता है। अत: विकल्प (b) सही है।

5. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये और सूचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

सूची-I (समिति)	**सूची-II (विषय)**
A. रंगराजन समिति	1. कर सुधार
B. नरसिम्हन समिति	2. बीमा सुधार
C. केलकर समिति	3. PSEs में शेयरों का विनिवेश
D. मल्होत्रा समिति	4. बैंकिंग क्षेत्र में सुधार

कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	2	4	1	3
(c)	3	4	1	2
(d)	3	1	4	2

उत्तर: (c)
व्याख्या: रंगराजन समिति विनिवेश संबंधी सुधारों के लिये 1993 में गठित की गई। इस समिति ने विनिवेश के चार तरीकों के अंतर्गत व्यापार बिक्री, रणनीतिक बिक्री, शेयरों का प्रस्ताव तथा परिसंपत्तियों को बेचना या बंद करना जैसे उपाय सुझाए।

- नरसिम्हन समिति-I (1991) और नरसिम्हन समिति-II (1998) का गठन भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था।
- कर संरचना सुधार हेतु 2002 में विजय केलकर के नेतृत्व में केलकर समिति का गठन हुआ।
- मल्होत्रा समिति का गठन बीमा क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा हेतु 1993 में आर-एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में किया गया। मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर ही बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) का गठन 19 अप्रैल, 2000 को किया गया। अत: विकल्प (c) सही है।

7 आर्थिक नियोजन (Economic Planning)

1. पूर्वोत्तर परिषद (नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल) का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है?
   (a) भारत के राष्ट्रपति
   (b) भारत के प्रधानमंत्री
   (c) केंद्रीय गृहमंत्री
   (d) केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

उत्तर: (c)
व्याख्या: पूर्वोत्तर परिषद (नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल) की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई थी। इसके सदस्य पूर्वोत्तर के आठ राज्य यथा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा हैं। इसकी स्थापना भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु की गई, जिसके पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृहमंत्री होते हैं। अत: विकल्प (c) सही है।

2. 'समावेशी संवृद्धि', जो एक सूक्ति है, भारत की किस/किन योजना/योजनाओं में प्रयुक्त हुई है?
   1. नवीं योजना
   2. दसवीं योजना
   3. ग्यारहवीं योजना
   4. बारहवीं योजना

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।
   (a) 1, 2 और 3 (b) 2 और 4
   (c) 3 और 4 (d) केवल 4

उत्तर: (c)
व्याख्या: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) का उद्देश्य विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना और समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करना था तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) का उद्देश्य तीव्र, धारणीय एवं समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति थी। अत: विकल्प (c) सही है।

3. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. के. एन. राज के नेतृत्व में इसका प्रारूप तैयार किया गया।
   2. इसमें प्रस्ताव था कि बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योग पब्लिक सेक्टर में विकसित किए जाएँ।
   3. प्रारूपकारों ने पाया कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना बहुत कठिन है।
   4. प्रारूपकारों ने पाया कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना वास्तव में आसान है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) 1 और 2
   (c) 2 और 3 (d) 3 और 4

उत्तर: (c)
व्याख्या: द्वितीय पंचवर्षीय योजना 'पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके अंतर्गत उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के प्रारूपकारों ने पाया कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना एक कठिन कार्य है।
- ध्यातव्य है कि के.एन. राज के नेतृत्व में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। अत: विकल्प (c) सही है।

4. निम्नलिखित घटनाओं को भारत में उनके घटने के सुसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिये-
   1. महालनोबिस मॉडल
   2. योजना छुट्टी
   3. आवर्ती योजना (रोलिंग प्लान)

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।
   (a) 1, 2, 3 (b) 3, 2, 1
   (c) 2, 3, 1 (d) 1, 3, 2

उत्तर: (a)
व्याख्या: द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-1961) 'पी.सी. महालनोबिस मॉडल' पर आधारित थी, जिसके अंतर्गत उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई।
- योजना छुट्टी अथवा योजना अवकाश (1966-1969) दौरान तीन वार्षिक योजनाएँ बनाई गई, ऐसा चीन तथा पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण किया गया था। 1978-83 की अवधि के लिये अनवरत योजना अथवा आवर्ती योजना (रोलिंग प्लान) बनाई गई, लेकिन 1980 में इसे समाप्त कर दिया गया। इस योजना का प्रतिपादन 'गुन्नार मिर्डल' द्वारा अपनी पुस्तक 'एशियन ड्रामा' में किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार और डी.टी. लकड़ावाला को जाता है। अत: विकल्प (a) सही है।

5. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   1. दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक ज़ोर दिया गया।
   2. चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया।
   3. पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, पहली बार, वित्तीय क्षेत्रक को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया।

   नीचे दिये गये कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
   (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

8 नीति आयोग (NITI Aayog)

1. समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है?
   (a) असमानता को घटाने पर
   (b) निर्धनता को घटाने पर
   (c) जनजातीय आबादी के लिये जीविका के विविधीकरण पर
   (d) निर्धन देशों को निकट लाने पर

उत्तर: (d)
व्याख्या: समाज के प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को संस्थागत तरीके से वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध करवाना ही समावेशन रणनीति है। निर्धन देशों को करीब लाना इस रणनीति का हिस्सा नहीं है। अत: विकल्प (d) सही है।

2. अटल नवप्रवर्तन (इनोवेशन) मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है?
   (a) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
   (b) श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
   (c) नीति (NITI) आयोग
   (d) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

उत्तर: (c)
व्याख्या: अटल नवप्रवर्तन (इनोवेशन) मिशन, नीति आयोग (NITI Aayog) की एक प्रमुख पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह देश की नवाचार और उद्यमशीलता से संबंधित भावी ज़रूरतों पर विस्तृत अध्ययन व विचार-विमर्श पर आधारित है।

3. नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. यह भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत 'थिंक टैंक' है, जो दिशात्मक और नीतिगत दोनों निविष्टियाँ प्रदान करता है।
   2. यह केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी परामर्श प्रदान करता है।
   3. यह राष्ट्रीय हित में राज्यों को एक साथ लाने के लिये भारत सरकार के मंच के रूप में कार्य करता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
   (a) केवल 2 और 3 (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)
व्याख्या: राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है) का गठन 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था।
- नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत 'विचार मंच' है, जो दिशात्मक और नीतिगत दोनों निविष्टि (इनपुट्स) प्रदान करता है। अत: कथन 1 सही है।
- भारत सरकार के लिये रणनीतिक व दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के साथ ही नीति आयोग, केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी परामर्श भी प्रदान करता है। अत: कथन 2 सही है।
- भारत सरकार ने अपने सुधार कार्यक्रमों पर आगे बढ़ते हुए 1950 में स्थापित 'योजना आयोग' को प्रतिस्थापित करने के लिये नीति आयोग का गठन किया। ऐसा सामयिक भारतीय आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये किया गया।
- अतीत की तुलना में एक उल्लेखनीय प्रगति दर्शाते हुए नीति आयोग राष्ट्रीय हित में राज्यों को भी साथ लाने के लिये भारत सरकार के एक उत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है और इस तरह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। अत: कथन 3 सही है।
- नीति आयोग के गठन के मूल में दो केंद्र हैं- टीम इंडिया केंद्र और ज्ञान एवं नवाचार केंद्र। टीम इंडिया केंद्र, केंद्र सरकार के साथ राज्यों की भागीदारी का नेतृत्व करता है, जबकि ज्ञान एवं नवाचार केंद्र नीति आयोग की चिंतन-समूह क्षमताओं का निर्माण करता है। ये दोनों केंद्र आयोग के दो महत्त्वपूर्ण कार्यों को दर्शाते हैं।
- नीति आयोग स्वयं को आवश्यक संसाधन, ज्ञान और कौशल के साथ अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है जो इसे तीव्र गति से कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के लिये रणनीतिक नीति दृष्टि प्रदान करने और अनिश्चित मुद्दों से निपटने में सक्षम बनाएगा।

4. निम्नलिखित में से कौन-से संगठन/संस्थान ने सामूहिक/स्वतंत्र रूप से स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (SEQI) विकसित किया है?
   1. नीति आयोग
   2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)
व्याख्या: मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और नीति आयोग ने संयुक्त रूप से एक 'स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक' का विकास किया है। इसका उपयोग स्कूली बच्चों की सीखने की क्षमता पर निगरानी और उसमें सुधार करने के लिये किया जाएगा।

5. भारत के विकास एजेंडे को बदलने के उद्देश्य से सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की है। निम्नलिखित में से कौन-से नीति आयोग के कार्य हैं?
   1. राज्यों के साथ संरचित समर्थन पहलों और तंत्रों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।

9 गरीबी (Poverty)

1. भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्दिष्ट करती है?
   (a) घरेलू बचत (b) घरेलू उपभोग
   (c) घरेलू निवेश (d) घरेलू आय

उत्तर: (b)

व्याख्या: भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) एक मुख्य संस्था के रूप में कार्य करता है। भारत में पूर्ण गरीबी को मापने के लिये घरेलू उपभोग विधि का प्रयोग किया जाता है। अत: विकल्प (b) सही है।

2. UNDP के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित 'बहुआयामी निर्धनता सूचकांक' में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सम्मिलित है/हैं?
   1. पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन
   2. राष्ट्रीय स्तर पर क्रय-शक्ति समता
   3. राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और GDP की विकास दर

   निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

व्याख्या: बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता मापक उपकरण है, जिसे ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा यूएनडीपी की फ्लैगशिप मानव विकास रिपोर्ट के लिये विकसित किया गया है। इस सूचकांक को 2010 में विकसित किया गया था और इसे यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट, 2010 में शामिल किया गया था। इस सूचकांक में कुल 10 संकेतक सम्मिलित हैं:

- शिक्षा, जिसमें स्कूलिंग का वर्ष और विद्यालय में उपस्थिति शामिल हैं।
- स्वास्थ्य, जिसमें बाल मृत्यु व कुपोषण शामिल हैं।
- जीवन स्तर, जिसमें शामिल हैं-
  - विद्युत सुविधा का अभाव
  - पेयजल का अभाव
  - स्वच्छता (Sanitation) का अभाव
  - अस्वच्छ फर्श (Flooring)
  - खाना पकाने के ईंधन का अभाव
  - परिसंपत्तियों (Assets), जैसे- टीवी टेलीफोन, बाइक, मोटरबाइक, रेफ्रिजरेटर, कार अथवा ट्रैक्टर का अभाव।

इस प्रकार कुल तीन श्रेणियों- शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के तहत कुल 10 संकेतकों के आधार पर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को मापा जाता है।

3. ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDAs) भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं?
   1. DRDAs देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं।
   2. DRDAs विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उनके समाधान के विस्तृत उपाय तैयार करते हैं।
   3. DRDAs निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतरक्षेत्रीय (इंटर-सेक्टोरल) तथा अंतरविभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित करते हैं।
   4. DRDAs निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों के लिये मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 3 और 4
   (c) केवल 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

व्याख्या: ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन मूल रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) के क्रियान्वयन के लिये किया गया था। ये अभिकरण निम्नांकित रूपों में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में मदद करते हैं:

- निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करके।
- विभिन्न अन्य अभिकरणों व विभागों, जैसे- पंचायती राज संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ प्रभावी तरीके से समन्वय स्थापित करना ताकि ज़िला स्तर पर निर्धनता उन्मूलन के लिये आवश्यक संसाधन व समर्थन प्राप्त किया जा सके।
- यह केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है।
- निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों के लिये मिले कोष के प्रभावी और निष्पक्ष उपयोग पर निगरानी तथा पारदर्शिता।
- ग्रामीण विकास व निर्धनता उन्मूलन के संबंध में जागरूकता स्तर में सुधार को सुनिश्चित करना।
- रिपोर्टिंग व क्षेत्र भ्रमणों (field visits) के ज़रिये कार्यक्रमों पर सुदृढ़ निगरानी रखते हैं। ये अभिकरण ज़िला परिषद, केंद्र व राज्य सरकार को निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में निश्चित अवधि पर सूचना देकर अवगत कराते रहते हैं।
- ज़िले के लिये निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों हेतु हस्तांतरित सभी कोषों की प्रभावी उपयोगिता सुनिश्चित करना।

10 बेरोज़गारी (Unemployment)

1. 'नेशनल करियर सर्विस' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. नेशनल करियर सर्विस, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, का एक उपक्रमण है।
   2. नेशनल करियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर के संवर्धन के लिये मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)
व्याख्या: 'नेशनल करियर सर्विस' (NCS) परियोजना एक मिशन मोड परियोजना के रूप में भारत के श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है।
- यह पोर्टल मुख्य रूप से युवाओं की आकांक्षाओं के साथ अवसरों को जोड़ने के लिये विकसित किया गया है। साथ ही, यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों, नौकरी प्रदाताओं, कौशल प्रदाताओं, कॅरियर सलाहकारों आदि के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। अत: दोनों कथन गलत हैं।

2. निम्नलिखित में से कौन 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम' के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है?
   (a) केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के वयस्क सदस्य
   (b) गरीबी रेखा से नीचे के (BPL) परिवारों के वयस्क सदस्य
   (c) सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य
   (d) किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य

उत्तर: (c)
व्याख्या: 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम' को यह नाम 2 अक्तूबर, 2009 को मिला। इसके पूर्व यह नरेगा के नाम से जाना जाता था जिसकी शुरुआत 2 फरवरी, 2006 को की गई थी। यह योजना भारत में बिना वर्गीय भेदभाव किये प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिवसों की गारंटीशुदा मज़दूरी/रोज़गार प्रदान करती है। इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभाती हैं।

3. बेरोज़गारी उस समय विद्यमान कही जाती है, जब-
   (a) किसी डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वेतन और कार्य नहीं मिलता।
   (b) किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुरूप काम नहीं मिलता।
   (c) लोग प्रचलित मज़दूरी की दर से कम मज़दूरी पर कार्य करते हैं।
   (d) प्रचलित मज़दूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोज़गार नहीं मिलता।

उत्तर: (d)
व्याख्या: बेरोज़गारी उस समय विद्यमान कही जाती है, जब प्रचलित मज़दूरी की दर पर काम करने के लिये इच्छुक लोगों को रोज़गार प्राप्त नहीं होता।

4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) के संदर्भ में नीचे दिये गए कथनों पर विचार कीजिये-
   1. यह अधिनियम एक-तिहाई रोज़गार महिलाओं के लिये सुरक्षित करने का प्रावधान करता है।
   2. इसका उद्देश्य किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को, जो अकुशल श्रम के लिये तैयार हों, कम-से-कम 100 दिनों का सुनिश्चित रोज़गार प्रदान करना है।
   3. इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवदेक को 30 दिन के अंदर रोज़गार उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सत्य हैं?
   (a) केवल 1 और 2
   (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3
   (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (a)
व्याख्या: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) का उद्देश्य किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को, जो अकुशल श्रम के लिये तैयार हों, 100 दिनों के रोज़गार (सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों का रोज़गार) की गारंटी प्रदान करना है। अत: कथन 2 सत्य है।
- इस प्रावधान के तहत एक-तिहाई रोज़गार महिलाओं के लिये सुरक्षित किये गए हैं। अत: कथन 1 सत्य है।
- मनरेगा के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोज़गार भत्ते का हकदार होगा। अत: कथन 3 असत्य है।

5. बेरोज़गारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि-
   (a) गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है।
   (b) जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है।
   (c) मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है।
   (d) ब्याज़ दर बढ़ती है।

11

खाद्य सुरक्षा
(Food Security)

1. निम्नलिखित में से कौन-सा/से वह/वे सूचक है/हैं, जिसका/जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया गया है?
   1. अल्प-पोषण
   2. शिशु वृद्धिरोधन
   3. शिशु मृत्यु-दर

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
   (c) 1, 2 और 3 (d) केवल 1 और 3

उत्तर: (c)
व्याख्या: वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) रिपोर्ट को विश्व स्तर पर भुखमरी को मापने एवं ट्रैक करने के लिये तैयार किया जाता है। जीएचआई की रिपोर्ट वैश्विक स्तर के साथ-साथ देशों और क्षेत्रीय हिस्सों को भी दायरे में लेती है। इस सूचकांक की गणना प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) द्वारा की जाती है। जीएचआई के माध्यम से भुखमरी खत्म करने एवं पोषण का स्तर बढ़ाने का संदेश विश्व स्तर पर दिया जाता है।
- वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) रिपोर्ट तैयार करने में निम्नलिखित चार सूचकों का उपयोग किया जाता है:
  - अल्प-पोषण
  - शिशु-वृद्धिरोधन
  - शिशु-मृत्यु दर
  - लंबाई के अनुपात में कम वज़न

2. भारतीय खाद्य निगम के लिये खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किये गए बोनस (यदि कुछ है) के साथ-साथ और क्या शामिल है/हैं?
   (a) केवल परिवहन लागत
   (b) केवल ब्याज़ लागत
   (c) प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत
   (d) प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा गोदामों के प्रभार

उत्तर: (c)
व्याख्या: भारतीय खाद्य निगम (FCI) के लिये खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और किसानों को भुगतान किये गए बोनस के साथ-साथ प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स और डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट शामिल हैं।
आर्थिक लागत = किसानों को देय न्यूनतम समर्थन मूल्य + खरीद संबंधी सहायक खर्च + वितरण लागत

3. भारत सरकार 'मेगा फूड पार्क' की अवधारणा को किन-किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है?
   1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिये उत्तम अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु।
   2. खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु।
   3. उद्यमियों के लिये उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध कराने हेतु।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)
व्याख्या: भारत सरकार 'मेगा फूड पार्क' की अवधारणा को निम्न उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है:
- देश में एक सुदृढ़ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना।
- प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिये प्रभावी आपूर्ति शृंखला का गठन।
- संग्रहण केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों और कोल्ड चेन अवसंरचनाओं के रूप में खाद्य प्रसंस्करण के लिये आधुनिक अवसंरचनाओं का गठन।
- खाद्य अपशिष्टों का न्यूनीकरण करते हुए कृषकों की आजीविका में सुधार।
- एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ कृषि क्षेत्र से बाज़ार तक एक मूल्य शृंखला तैयार करना।
- हब और स्पोक मॉडल के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास।

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो 'गरीबी रेखा से नीचे' (बी.पी.एल.) श्रेणी में आते हैं।
   2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किये जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी।
   3. गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) 1 और 2 (b) केवल 2
   (c) 1 और 3 (d) केवल 3

12 मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र (Inflation and the Business Cycle)

1. भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है?
   (a) प्राथमिक वस्तु (b) ईंधन और शक्ति
   (c) विनिर्मित उत्पाद (d) खाद्य मद

उत्तर: (c)
व्याख्या: थोक कीमत सूचकांक वस्तुओं के थोक मूल्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इस सूचकांक का संकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक स्तर पर होता है, जो पहले साप्ताहिक स्तर पर होता था। साथ ही, इसका आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। इस संशोधित शृंखला में विनिर्मित उत्पादों का भारांश 64.23 प्रतिशत है। विदित हो कि इस सूचकांक में सेवाएँ शामिल नहीं हैं। अत: विकल्प (c) सही है।

2. भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है?
   (a) भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है।
   (b) मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिज़र्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है।
   (c) घटा हुआ मुद्रा परिचलन (मनी सर्कुलेशन) मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है।
   (d) बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है।

उत्तर: (c)
व्याख्या: घटा हुआ मुद्रा परिचलन (मनी सर्कुलेशन) मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। विकल्प (a) तथा (b) गलत हैं, क्योंकि सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों क्रमश: अपनी राजस्व नीति एवं मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का प्रयास करते हैं। विकल्प (d) भी असत्य है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि के बिना मुद्रा प्रसार में वृद्धि से तरलता बढ़ने के चलते स्फीतिकारी दबाव बढ़ जाता है और मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता नहीं मिल पाती। अत: विकल्प (c) सही है, क्योंकि मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा आपूर्ति में कमी के प्रयास किये जाते हैं।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुँचाती है।
   2. मुद्रास्फीति बॉण्डधारकों को लाभ पहुँचाती है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)
व्याख्या: मुद्रास्फीति के चलते क्रयशक्ति में कमी के कारण ऋणदाता वर्ग (Lender) हानि की स्थिति में होता है जबकि ऋणी (Debtors) को लाभ प्राप्त होता है। क्रयशक्ति में गिरावट के कारण ऋणदाता को जो ब्याज़ तथा मूलधन के रूप में रुपया मिलता है, उसकी क्रयशक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। इसलिये ऋणदाता को हानि होती है पर ऋणी को लाभ होता है क्योंकि वस्तु के रूप में उन्हें कम ही भुगतान देना पड़ता है।
विकल्प (b) सही नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति सामान्य बॉण्डधारकों को लाभ नहीं पहुँचाती। बॉण्डधारक से आशय है- जिन्होंने बॉण्ड के एवज़ में रुपया (कोई भी मुद्रा) उधार दे दिया है। मुद्रास्फीति की दशा में ये नुकसान की स्थिति में रहेंगे। अत: विकल्प (b) गलत है। मुद्रास्फीति मुद्रा/धन की क्रय शक्ति को कमज़ोर कर देती है। अधिकांश ऋण उत्पाद (Debt Products), जैसे- सावधि जमा (Fixed deposits) अथवा नियमित बॉण्ड (Regular Bonds) जो रिटर्न प्रदान करते हैं, वे मुद्रास्फीति के संदर्भ में संरक्षित नहीं होते।

4. भारत में मुद्रास्फीति की दर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके उतार-चढ़ाव के संदर्भ में मापी जाती है?
   (a) उपभोक्ता कीमत सूचकांक
   (b) थोक कीमत सूचकांक
   (c) उपभोक्ता कीमत सूचकांक एवं थोक कीमत सूचकांक दोनों
   (d) मुद्रा पूर्ति

उत्तर: (c)
व्याख्या: भारत में पहले मुद्रास्फीति की गणना केवल थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती थी, परंतु 2014 से यह गणना थोक कीमत सूचकांक एवं उपभोक्ता कीमत सूचकांक दोनों के आधार पर की जाती है। कीमत सूचकांक कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव की औसत प्रवृत्ति को मापते हैं। अत: विकल्प (c) सही है।

5. स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप्य कभी-कभी 'आधार प्रभाव' (Base Effect) पर लगाया जाता है। यह 'आधार प्रभाव' क्या है?
   (a) यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव का प्रभाव है
   (b) यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेज़ी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है
   (c) यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है
   (d) इस संदर्भ में उपर्युक्त (a), (b) तथा (c) कथनों में से कोई भी सही नहीं है

13 मुद्रा बाज़ार एवं बैंकिंग प्रणाली (Money Market and Banking System)

1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
   (a) वे वित्तीय संस्थान जो बैंक जैसा व्यवसाय तो करते हैं लेकिन जमाकर्त्ताओं को अपने खातों से धन की निकासी की अनुमति नहीं देते, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी कहलाते हैं।
   (b) भारत में आवासीय वित्त की शीर्षस्थ संस्था 'हुडको' है।
   (c) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मूल उद्देश्य कृषकों की सहायता करना है।
   (d) भारत में कार्यरत वाणिज्यिक बैंक अपनी तरलता आवश्यकताओं के लिये सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक से कर्ज नहीं ले सकते हैं।

उत्तर: (a)

व्याख्या: भारत में आवासीय वित्त की शीर्षस्थ संस्था राष्ट्रीय आवास बैंक है। अत: कथन (b) गलत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मूल उद्देश्य समाज के उन कमज़ोर वर्गों के लोगों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना है जिन्हें लक्ष्य समूह कहा जाता है। अत: कथन (c) गलत है। भारत में कार्यरत वाणिज्यिक बैंक अपनी तरलता आवश्यकताओं के लिये सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक से कर्ज़ ले सकते हैं। अत: कथन (d) भी गलत है।

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के इरादे से रेपो दर बढ़ाई जाती है।
   2. रेपो दर व्यवस्था में आरबीआई बैंकों से सरकारी बॉण्ड इस समझौते के साथ खरीदती है कि वह इसे बाद में निश्चित दर पर वापस कर देगी।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या: रिवर्स रेपो दर में वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से सरकारी बॉण्ड खरीदते हैं और आरबीआई इनके पास से अत्यधिक फंड कुछ ब्याज़ दर पर अपने पास ले लेती है जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। अत: मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिये रिवर्स रेपो दर बढ़ाई जाती है।

3. 'मुद्रा गुणक' का मान-
   1. कम बैंक दर के कारण बढ़ता है।
   2. एस.एल.आर. में बढ़ोतरी के कारण बढ़ता है।
   3. 1 से अधिक होता है।
   4. सीआरआर बढ़ने से घटता है।

   कूट:
   (a) केवल 3 (b) केवल 1, 2 और 4
   (c) केवल 1, 3 और 4 (d) केवल 1 और 3

उत्तर: (c)

व्याख्या: आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में धन निर्गमित किये जाने पर कुल मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से उच्च शक्ति मुद्रा की राशि में बढ़ोतरी होती है। ऐसा गुणक प्रभाव के कारण होता है।

- मुद्रा गुणक को अर्थव्यवस्था में मुद्रा भंडार और उच्च शक्ति मुद्रा भंडार के बीच अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका मान 1 से अधिक होता है।
- कम ब्याज़ दर के कारण बैंक अपने रिज़र्व के रूप में जमा का कम अनुपात रखने को उत्साहित होते हैं क्योंकि आरबीआई से ऋण लेना अब सस्ता पड़ता है। परिणामस्वरूप बैंक अपने संसाधनों का बड़ा भाग निवेशकों और कर्ज़दारों के ऋण के तौर पर देते हैं और इस प्रकार गुणक प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं।
- इसी प्रकार बदलती रिज़र्व आवश्यकताओं (अर्थात् सीआरआर और एसएलआर) में कमी से रिज़र्व जमा अनुपात में भी गिरावट आएगी जिससे गुणक के मान में वृद्धि होगी; जबकि सीआरआर और एसएलआर में वृद्धि से रिज़र्व जमा अनुपात में बढ़ोतरी होगी, जिससे मुद्रा गुणक के मान में गिरावट आएगी।

4. अर्थव्यवस्था 'तरलता संजाल' में तब होती है जब:
   (a) बॉण्ड पर दिया गया ब्याज़ दर न्यूनतम हो।
   (b) बॉण्ड पर दिया गया ब्याज़ दर अधिकतम हो।
   (c) मुद्रा का अंतरण मांग अधिकतम हो।
   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर: (a)

व्याख्या: तरलता संजाल एक ऐसी स्थिति होती है जब वर्तमान ब्याज़ दर कम हो और बचत दर अधिक हो जिससे मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती हो। तरलता संजाल में उपभोक्ता बॉण्ड नहीं रखना चाहता है और अपनी निधि को बचत के रूप में रखना चाहता है क्योंकि उसे यह लगता है कि ब्याज़ दर में जल्दी बढ़ोतरी होगी।

5. बैंक द्वारा उधार देने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है?
   (a) एमएसएमईडी एक्ट, 2006 के तहत खाद्य और कृषि प्रसंस्करण के लिये दिया गया ऋण।
   (b) गृह ऋण।
   (c) निर्यात ऋण।
   (d) फिक्की और एसोचैम जैसे संगठनों को ऋण।

14 भारत में बीमा और पूंजी बाज़ार (Insurance and Capital Market in India)

1. निम्नलिखित पर विचार कीजिये-
   1. होटल तथा रेस्तराँ
   2. मोटर परिवहन उद्योग
   3. समाचार पत्र प्रतिष्ठान
   4. निजी चिकित्सा संस्थान

   उपर्युक्त में से किस इकाई/किन इकाइयों के कर्मचारी, 'कर्मचारी राज्य बीमा योजना' के अंतर्गत 'सामाजिक सुरक्षा' कवच प्राप्त कर सकते हैं?
   (a) केवल 1, 2 और 3
   (b) केवल 4
   (c) केवल 1, 3 और 4
   (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

व्याख्या: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत भारत के कामगारों के लिये सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के प्रावधानों के अनुपालन में 24 फरवरी, 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना का उद्घाटन कानपुर (उ.प्र.) में किया गया था। निम्नलिखित इकाइयों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त है-

- निजी चिकित्सा एवं शैक्षणिक संस्थान।
- दुकान, होटल व रेस्तराँ।
- सिनेमा व प्रिव्यू थियेटर्स।
- मोटर परिवहन उद्योग।
- समाचार पत्र और विज्ञापन संस्थान, जहाँ 10 या अधिक व्यक्ति कार्य में लगे हों।

2. प्रतिभूति बाज़ारों के संदर्भ में 'ग्रीनशू ऑप्शन' (Greenshoe Option) क्या है?
   (a) सिस्टर कंपनियों में अंतरण मूल्य के निर्धारण हेतु निर्यात उत्पादों के कारक मूल्य का उपयोग करना।
   (b) पहली बार सूचीबद्ध कंपनी के लिये ओवर-एलॉटमेंट प्रावधान।
   (c) लघु एवं मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में नए उद्योगों के लिये विदेशी मुद्रा छूट।
   (d) दिवालियेपन के लिये दाखिल कंपनी द्वारा जारी क्रेडिट हेतु अनुमानित छूट।

उत्तर: (b)

व्याख्या: ग्रीनशू ऑप्शन:

- यह एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत पहली बार शेयर जारी करने वाली कंपनी को सार्वजनिक रूप से कुछ अतिरिक्त शेयर, आमतौर पर 15 प्रतिशत (जिसे अतिरिक्त-आवंटन प्रावधान के रूप में भी जाना जाता है) बेचने की अनुमति दी जाती है। यह नाम पहली कंपनी (ग्रीनशू कंपनी, यूएसए) के नाम पर रखा गया है, जिसे पहली बार ऐसा विकल्प दिया गया था।
- यदि शेयरों की सार्वजनिक मांग अपेक्षाओं से अधिक है और शेयर पेश की गई कीमत के ऊपर का कारोबार करता है, तो यह विकल्प अंडरराइटर्स को शेयरों की अतिरिक्त मांग से 15% अधिक शेयर खरीदने की अनुमति देता है।
- मुख्य रूप से उपर्युक्त विकल्प का उपयोग IPO या सफल शेयरों की कीमत सुनिश्चित करने हेतु किसी स्टॉक को सूचीबद्ध करते समय किया जाता है। तद्नुसार, कंपनियाँ सूचीबद्ध होने के तुरंत बाद 30 दिनों के समयांतराल के दौरान शेयर की कीमतों को स्थिर करने के लिये बाज़ार में हस्तक्षेप कर सकती हैं। यदि शेयर की वर्तमान कीमत उसे जारी करने के समय की कीमत के मुकाबले कम या काफी अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में अंडरराइटिंग सिंडिकेट द्वारा बाज़ार से इक्विटी शेयर खरीदे जा सकते हैं। उपर्युक्त विकल्प मूल्य स्थिरीकरण तंत्र के रूप में कार्य करता है। अत: विकल्प (b) सही है।

3. एक प्राथमिक प्रतिभूति बाज़ार है:
   (a) जहाँ केंद्रीय बैंक अपनी श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का व्यापार करता है।
   (b) जहाँ सार्वभौमिक बॉण्ड का व्यापार होता है।
   (c) जहाँ प्राथमिक उपकरण धारक अपनी प्रतिभूतियों का व्यापार करते हैं।
   (d) जहाँ जारीकर्त्ता कंपनी द्वारा पूंजी जुटाई जाती है।

उत्तर: (d)

व्याख्या: प्रत्येक सुरक्षा बाज़ार में दो पूरक बाज़ार होते हैं - प्राथमिक और द्वितीयक।

प्राथमिक बाज़ार

- जिस बाज़ार में सुरक्षा बाज़ार के लिखतों का व्यापार (खरीद) सीधे पूंजी- एकत्रक (capital-raiser) और लिखत क्रेता के बीच होता है, उसे प्राथमिक बाज़ार के रूप में जाना जाता है।
- इस बाज़ार का उपयोग कंपनियों द्वारा शेयर, बांड आदि जारी करके पूंजी जुटाने के लिये किया जाता है।
- उदाहरण के लिये, यदि जारीकर्त्ता (कंपनी खुद) से किसी व्यक्ति द्वारा सीधे शेयर खरीदे जा रहे हों तो उस व्यक्ति को प्राथमिक शेयरधारक के रूप में जाना जाता है।

द्वितीयक बाज़ार

- वह बाज़ार जहाँ प्राथमिक उपकरण धारकों के बीच सुरक्षा बाज़ार के लिखतों का व्यापार होता है, द्वितीयक बाज़ार के रूप में जाना जाता है।
- इस तरह के लेन-देन को उनके व्यापार के लिये एक संस्थागत मंच की आवश्यकता होती है जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अत: विकल्प (d) सही हैं।

15 राजकोषीय नीति एवं कर संरचना (Fiscal Policy and Tax Structure)

1. भारत में निगम-कर किसी कंपनी की आय पर लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सी मद में निगम-कर शामिल नहीं है?
   (a) व्यवसाय से लाभ
   (b) पूंजीगत अभिलाभ
   (c) प्रतिभूतियों पर ब्याज़
   (d) परिसंपत्तियों की विक्रय प्राप्ति

उत्तर: (d)
व्याख्या: निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है, जो कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है। इसी कारण से इसे कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है।
- केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्रित निगम कर की मदों में व्यवसाय से लाभ, पूंजीगत अभिलाभ तथा प्रतिभूतियों पर ब्याज़ शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर परिसंपत्तियों की विक्रय प्राप्ति, पूंजी लाभ कर का हिस्सा है। अत: विकल्प (d) सही है।

2. राजस्व घाटे से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिये अनुदानों को घटाने पर क्या प्राप्त होगा?
   (a) प्राथमिक घाटा
   (b) निवल राजकोषीय घाटा
   (c) बजटीय घाटा
   (d) प्रभावी राजस्व घाटा

उत्तर: (d)
व्याख्या: राजस्व घाटे में केंद्र सरकार के ऐसे व्यय शामिल होते हैं, जो वह राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में देती है। इससे कई विकासशील परिसंपत्तियों का सृजन होता है। अत: प्रभावी राजस्व घाटे की प्राप्ति केंद्र सरकार के राजस्व घाटे में से उसके पूंजीगत परिसंपत्तियों संबंधी अनुदानों को घटाने से होती है। अत: विकल्प (d) सही है।

3. किसी देश की, कर से GDP के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है?
   1. आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना
   2. राष्ट्रीय आय का कम साम्यिक (एक्विटेबल) वितरण

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)
व्याख्या: कर से GDP के अनुपात (Tax to GDP ratio) में कमी का अर्थ है कि GDP के अनुपात में कर संग्रहण की मात्रा में कमी। आर्थिक विकास दर धीमी होने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का कुल संग्रहण कम हो जाता है। अत: केवल कथन 1 सही है।

4. साल-दर-साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी कार्रवाई/कार्रवाइयाँ की जा सकती है/हैं?
   1. राजस्व व्यय को घटाना
   2. नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारम्भ करना
   3. सहायिकी (सब्सिडी) को युक्तिसंगत बनाना
   4. आयात शुल्क को कम करना

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3
   (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)
व्याख्या: साल-दर-साल लगातार घाटे का बजट रहा है। इस घाटे को कम करने के लिये सरकार द्वारा राजस्व व्यय को कम किया जाना तथा सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास करना जैसे उपाय शामिल हैं। नवीन कल्याणकारी योजनाओं का प्रारम्भ एवं आयात-शुल्क को कम करना, बजट घाटे को कम करने हेतु की जाने वाली कार्रवाइयाँ नहीं हैं। अत: कथन 1 और 3 सत्य हैं।

घाटे के बजट को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता है-
- गैर-ज़रूरी सब्सिडी को खत्म किया जाए तथा बाकी सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया जाए।
- राजस्व व्यय को भी कम किया जाना चाहिये।
- कर संरचना में सुधार किया जाना चाहिये।
- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लाभ में वृद्धि करनी होगी।
- काले धन की वापसी एवं गैर-निष्पादनकारी संपत्तियों की पहचान कर उन्हें अर्थव्यवस्था में लगाना।
- सरकारी दफ्तरों एवं मंत्रियों पर होने वाले बड़े-बड़े खर्चों को भी थोड़ा कम करके बजट घाटे में सुधार किया जा सकता है।

5. निम्नलिखित में से किसको/किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है?
   1. सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय
   2. विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण
   3. राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

16 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): क्यों, क्या और कैसे?
(Goods and Services Tax (GST) : Why,What and How?)

1. GST लाने के लिये सांविधानिक संशोधन की आवश्यकता क्यों थी?
   (a) संविधान में संशोधन के बिना GST लाने के लिये संघ के साथ सहमत होने के लिये राज्य तैयार नहीं थे।
   (b) GST समवर्ती आधार पर कार्यान्वित होना था और अनुच्छेद-246 ऐसे मामले के लिये अपर्याप्त था।
   (c) वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति ने सांविधानिक संशोधन की संस्तुति की थी।
   (d) GST परिषद ने सांविधानिक संशोधन की संस्तुति की थी ताकि उनकी शक्ति में वृद्धि हो।

उत्तर: (b)
व्याख्या: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के द्वारा अनुच्छेद-366 में एक नया खंड (12A) जोड़ा गया, जिसके अनुसार 'वस्तु एवं सेवा कर' का अर्थ है- मानव उपभोग के लिये मादक पेय पदार्थों की आपूर्ति पर लगने वाले कर को छोड़कर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगने वाला कर। यह 1 जुलाई, 2017 से लागू कर दिया गया है। ध्यातव्य है कि जीएसटी समवर्ती आधार पर कार्यान्वित होना था और अनुच्छेद-246 (ससंद और राज्यों के विधान-मंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों की विषय-वस्तु) ऐसे मामले के लिये अपर्याप्त था, इसलिये सांविधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद-246 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि संसद को सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा और राज्यों को एसजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। अत: विकल्प (b) सही है।

2. निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिये-
   1. छिलका उतरे हुए अनाज
   2. मुर्गी के अंडे पकाए हुए
   3. संसाधित और डिब्बाबंद मछली
   4. विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र

   उपर्युक्त मदों में से कौन-सा/से जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत छूट प्राप्त है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)
व्याख्या: जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत निम्नलिखित तीन वस्तुएँ- छिलका उतरा हुआ अनाज, मुर्गी के अंडे पकाए हुए तथा विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र को छूट प्राप्त है, अर्थात् इन पर कोई टैक्स/कर नहीं लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी से छूट प्राप्त अन्य वस्तुओं में ताज़े फल व सब्ज़ियाँ, अनाज, फ्रेस मीट, बिंदी, सिंदूर, दूध, प्राकृतिक शहद, आटा, बेसन, स्टैम्प, कागज़ तथा हैंडलूम एवं प्रसाद शामिल हैं।

3. 'वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स-GST)' के क्रियान्वित किये जाने का/के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है/हैं?
   1. यह भारत में बहु-प्राधिकरणों द्वारा वसूल किये जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाज़ार स्थापित करेगा।
   2. यह भारत के 'चालू खाता घाटे' को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा।
   3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और आकार को बृहद् रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)
व्याख्या: वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा पूरे देश में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित एकल कर के रूप में विकसित की गई है, जबकि चालू खाते घाटे का संबंध व्यापार संतुलन से है। जीएसटी को लागू किये जाने से भारत की अर्थव्यवस्था को अवश्य ही मज़बूती मिलेगी, किंतु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि यह भविष्य में चीन से आगे होगी।

4. जीएसटी ई-वे बिल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. यह ₹50,000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं के केवल अंतर-राज्यीय लेन-देन को ट्रैक करने के लिये तकनीकी ढाँचा प्रदान करता है।
   2. वस्तुओं के अंतर-राज्यीय लेन-देन के लिये प्रत्येक राज्य हेतु अलग पारगमन पास की आवश्यकता होगी।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (c)
व्याख्या: नए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में 10 किमी. से अधिक दूरी की बिक्री के लिये ₹50,000 से अधिक मूल्य के वस्तु के राज्य के भीतर तथा अंतर-राज्यीय लेन-देन को ट्रैक करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल या 'ई-वे बिल' प्रणाली तकनीकी ढाँचा प्रदान करती है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- ई-वे बिल प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिये अलग-अलग पारगमन पास की आवश्यकता नहीं है। वस्तु के लेन-देन के लिये पूरे देश में एक ई-वे बिल वैध होगा। अत: कथन 2 सही नहीं है।

17 निवेश मॉडल (Investment Model)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
   1. प्रत्याशित निवेश में किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिये आय तथा रोज़गार के स्तर पर निवेश करने की इच्छा निवेशकर्त्ता रखता है।
   2. निवेश वस्तुएँ जैसे कि मशीन को भी अंतिम वस्तुओं में शामिल किया जाता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)
व्याख्या: उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं।
- निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक (जैसे कि मशीन, भवन, सड़क इत्यादि) में वृद्धि और उत्पादक माल-सूची (तैयार माल का स्टॉक) में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। योजनागत निवेश के मूल्य को प्रत्याशित निवेश कहते हैं।
- उत्पादकों का निवेश संबंधी निर्णय जैसे कि नए मशीन की खरीद, अधिकांशत: ब्याज़ की बाज़ार दर पर निर्भर करता है। प्रत्याशित निवेश मांग को हम इस प्रकार लिख सकते हैं:

$$\boxed{I = \bar{I}}$$

- जहाँ, $\bar{I}$ धनात्मक स्थिरांक है। $\bar{I}$ दिये हुए वर्ष में अर्थव्यवस्था में स्वायत्त (दिया हुआ अथवा बहिर्जात) निवेश को प्रदर्शित करता है।

2. निम्नलिखित में से कौन-से कारक निवेश की मात्रा को निर्धारित करते हैं?
   1. अर्थव्यवस्था का आकार 2. वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात
   3. बचत की सीमांत प्रवृत्ति 4. तकनीक

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये–
   (a) केवल 2 और 3 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)
व्याख्या: किसी अर्थव्यवस्था में एक समयावधि में कितने निवेश की आवश्यकता होगी या निवेश का क्या आकार होगा, यह निम्नांकित कारकों पर निर्भर करता है–
- अर्थव्यवस्था का आकार
- आर्थिक संवृद्धि की लक्षित दर
- वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात
- बचत की सीमांत प्रवृत्ति
- जनसंख्या वृद्धि दर
- तकनीक

अत: विकल्प (d) सही है।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
   1. पूंजी निर्गत अनुपात पूंजी की उत्पादकता को प्रदर्शित करता है।
   2. पूंजी निर्गत अनुपात पूंजी की उत्पादकता में विपरीत संबंध पाया जाता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)
व्याख्या: पूंजी निर्गत अनुपात पूंजी की उत्पादकता को प्रदर्शित करता है। यदि पूंजी निर्गत अनुपात 4 : 1 है, तो यह कहा जा सकता है कि उत्पाद की 1 इकाई उत्पादित करने के लिये पूंजी की 4 इकाइयों की आवश्यकता होती है। अत: कथन 1 सही है।
- पूंजी-निर्गत अनुपात और पूंजी की उत्पादकता में विपरीत संबंध होता है। यदि पूंजी निर्गत अनुपात अधिक है तो पूंजी की उत्पादकता कम होती है और यदि यह कम है, तो पूंजी की उत्पादकता अधिक होती है। अत: कथन 2 सही है।

अत: विकल्प (c) सही है।

4. निम्नलिखित में से कौन-सी हैरॉड-डोमर मॉडल की सीमाएँ हैं?
   1. सटीक पूंजी निर्गत अनुपात की गणना
   2. केवल पूंजीगत वस्तुओं को प्राथमिकता प्रदान करना
   3. श्रम और पूंजी में स्थिर संबंध
   4. बचत एवं निवेश को अत्यधिक महत्त्व

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये–
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)
व्याख्या: हैरॉड-डोमर मॉडल की सीमाएँ-
- भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग असंगठित है। इसलिये भारत में सटीक पूंजी निर्गत अनुपात ज्ञात करना थोड़ा कठिन है।
- इस मॉडल में पूंजीगत वस्तुओं पर अधिक ध्यान दिया गया है और उपभोक्ता वस्तुओं की अनदेखी की गई है।
- यह मॉडल श्रम और पूंजी में स्थिर संबंध मानता है लेकिन भारत जैसे देशों में श्रम एवं पूंजी दोनों एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकते हैं।
- यह मॉडल बचत पर विशेष ज़ोर देता है लेकिन भारत जैसे राष्ट्रों में बचत की दर को आवश्यकतानुसार समायोजित करने में काफी कठिनाइयाँ सामने आती हैं।

अत: विकल्प (d) सही है।

18 भारत का वैदेशिक क्षेत्र (External Sector of India)

1. निम्नलिखित में से कौन-सा, भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है?
   (a) वस्तुओं का निर्यात और आयात
   (b) सेवाओं का निर्यात और आयात
   (c) आय प्राप्तियाँ और भुगतान
   (d) पूंजीगत प्राप्तियाँ और भुगतान

उत्तर: (d)

व्याख्या: भुगतान संतुलन में किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन-देन का विवरण दर्ज होता है। भुगतान संतुलन के दो मुख्य खाते होते हैं-

- चालू खाता और पूंजी खाता।
- चालू खाते में वस्तुओं के आयात-निर्यात, सेवाओं और अंतरण अदायगियों के विवरण दर्ज होते हैं।
- पूंजी खातों में परिसंपत्तियों जैसे- मुद्रा, स्टॉक, बंधपत्र आदि का विवरण होता है। अत: विकल्प (d) सही है।

2. मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा, यदि
   (a) घरेलू सामान के मूल्य स्थिर रहें
   (b) आयातकों के लिये निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाएँ
   (c) आयात के मूल्य स्थिर रहें
   (d) निर्यात के मूल्य समानुपाती रूप से बढ़ें

उत्तर: (b)

व्याख्या: अवमूल्यन, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जान-बूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है। अवमूल्यन के माध्यम से किसी देश द्वारा अपने निर्यातों को बढ़ाया जाता है तथा आयातों में कमी लाई जाती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी देश के आयातकों के लिये निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाएँ तो मुद्रा का अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा। अत: विकल्प (b) सही है।

3. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारतीय रुपये की परिवर्तनीयता के संदर्भ में सही है?
   (a) यह पूंजी लेखा पर परिवर्तनीय है
   (b) यह चालू लेखा पर परिवर्तनीय है
   (c) यह चालू और पूंजी लेखा दोनों पर परिवर्तनीय है
   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: उदारीकरण की प्रक्रिया के तहत भारतीय रुपये की परिवर्तनीयता की दिशा में 19 अगस्त, 1994 को चालू लेखा के संदर्भ में रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया, परंतु पूंजी लेखा के संदर्भ में रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय न बनाकर आंशिक रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया है। अत: विकल्प (c) सही है।

4. भारत के संदर्भ में, मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस/किन कारक/कारकों का योगदान है?
   1. भारत के IT सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का
   2. सरकारी व्यय के बढ़ने का
   3. विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1
   (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 2
   (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या: भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित कारकों का योगदान है-

- भारत के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक (IT Sector) का विदेशी मुद्रा अर्जन।
- विदेशस्थ भारतीयों (Indians abroad) द्वारा भेजा गया धन।

ध्यातव्य है कि IT सेक्टर द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजा गया धन देश में विदेशी मुद्रा अंतर्वाह (Foreign Currency Inflow) को बढ़ाकर विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने के साथ भुगतान संतुलन (Balance of Payment) के घाटे को कम करता है जिससे मुद्रा संकट का जोखिम कम होता है।

- जबकि सरकारी व्यय के बढ़ने से यदि रुपये की आपूर्ति बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में रुपये का मूल्य गिरने से मुद्रा संकट का जोखिम और बढ़ सकता है। अत: दिये गए विकल्पों में विकल्प (b) सही उत्तर है।

5. पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को, जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाज़ार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है?
   (a) जमा प्रमाण पत्र
   (b) वाणिज्यिक पत्र
   (c) वचन पत्र (प्रॉमिसरी नोट)
   (d) सहभागिता पत्र (पार्टिसिपेटरी नोट)

19 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, समूह एवं समझौते (International Economic Organizations, Groups and Agreements)

1. निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य नहीं है?
   (a) फ्राँस (b) जर्मनी
   (c) रूस (d) जापान

उत्तर: (c)
व्याख्या: G7 दुनिया की सात सबसे बड़ी, विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इसके सदस्य देश कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। विदित हो कि 1998 में रूस के इस संगठन में शामिल होने से G7 परिवर्तित होकर G8 बन गया था, लेकिन 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के बाद रूस को इस समूह से निलंबित कर दिया गया था। अत: विकल्प (c) सही है।

2. दिसंबर 1985 में हस्ताक्षरित SAARC चार्टर पर निम्नलिखित में से किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किये थे?
   (a) अफगानिस्तान (b) श्रीलंका
   (c) पाकिस्तान (d) मालदीव

उत्तर: (a)
व्याख्या: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation - SAARC) दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इस समूह में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। 2007 से पहले सार्क के सात सदस्य थे, अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका आठवाँ सदस्य बना। अत: विकल्प (a) सही है।

3. विश्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. विश्व बैंक 1946 में स्थापित किया गया जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
   2. विश्व बैंक समूह ने 2030 तक विश्व से चरम गरीबी समाप्त करने को अपना लक्ष्य निर्धारित किया है।
   3. विश्व बैंक विश्व भर में विकासशील देशों के लिये वित्तीय और तकनीकी सहायता का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। यह सामान्य अर्थों में एक बैंक नहीं है, बल्कि गरीबी को कम करने और विकास को प्रोत्साहन देने की एक अनन्य साझेदारी है।
   4. विश्व बैंक समूह, हर देश के निचले स्तर के 40% लोगों की आय वृद्धि को प्रोत्साहन देते हुए साझी समृद्धि को बढ़ाने के लिये अपने सदस्य देशों द्वारा प्रबंधित पाँच संस्थाओं से मिलकर बनता है।

   उपर्युक्त कथनों में से सही हैं?
   (a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4
   (c) 1, 3 और 4 (d) केवल 2 और 4

उत्तर: (b)
व्याख्या: संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष अभिकरण का दर्जा प्राप्त 'विश्व बैंक समूह' विश्व का प्रमुख आर्थिक संगठन है। इसकी शुरुआत 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन, जिसे सामान्यत: ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से हुई। इसके अंतर्गत पाँच संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD), अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC), बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA) और निवेश विवादों के समाधान के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID) शामिल हैं। अत: विकल्प (b) सही है।

4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
   1. IMF संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण है।
   2. IMF को अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिये 1944 में हुए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में स्थापित किया गया।
   3. IMF का उद्देश्य मुद्रा विनिमय दरों को स्थिरता प्रदान करना तथा अंतर्राष्ट्रीय तरलता का विस्तार करना (दुर्लभ मुद्राओं तक पहुँच बनाना) है।

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) 1, 2 और 3
   (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 2
   (d) केवल 1 और 3

उत्तर: (a)
व्याख्या: ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णयानुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की औपचारिक स्थापना 27 दिसंबर, 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुई थी, लेकिन इसने वास्तविक रूप में 1 मार्च, 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया। यह संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट अभिकरण है, जिसकी प्रमुख ज़िम्मेदारियों में सदस्य देशों की मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना; बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था स्थापित करके विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना अथवा कम करना जैसे मुद्दे शामिल हैं। अत: विकल्प (a) सही है।

5. विश्व व्यापार संगठन (WTO) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. WTO राष्ट्रों के बीच व्यापार के विश्वव्यापी नियमों से संबंध रखता है।
   2. WTO का लक्ष्य माल एवं सेवाओं के उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों को उनके व्यापार संचालन में सहायता करना है।

20 जनसांख्यिकीय सिद्धांत और जनगणना (Demographic Theory and Census)

1. किसी देश के 'जनसांख्यिकीय लाभांश' की घटना किससे संबंधित है?
   (a) कुल जनसंख्या में तीव्र पतन (गिरावट)
   (b) श्रमजीवी काल (कार्यकारी आयु) वाली जनसंख्या में वृद्धि
   (c) शिशु मृत्यु दर में गिरावट
   (d) स्त्री-पुरुष अनुपात में वृद्धि

उत्तर: (b)

व्याख्या: किसी देश के जनसंख्या ढाँचे में आश्रित जनसंख्या (14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों के साथ-साथ 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग) की तुलना में बढ़ती कार्यशील जनसंख्या (15-64 वर्ष), जो अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के विकास को दर्शाती है, को जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। भारत जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में है। अत: विकल्प (b) सही है।

- ध्यातव्य है कि 2011 की जनगणना में 15 से 59 वर्ष के आयु के वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में रखा गया था जबकि वर्तमान में LFPR, OECD एवं विश्व बैंक के अनुसार 15-64 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या माना जाता है।

2. जनांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिये भारत को क्या करना चाहिये?
   (a) कुशलता विकास का प्रोत्साहन
   (b) और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रारंभ
   (c) शिशु मृत्यु दर में कमी
   (d) उच्च शिक्षा का निजीकरण

उत्तर: (a)

व्याख्या: जनांकिकीय लाभांश से आशय भारत जैसे देश में 15-64 वर्ष आयु वर्ग की कार्यशील जनसंख्या की अधिकता से है, किंतु यह जनांकिकीय लाभांश सही अर्थों में तभी सार्थक हो पाएगा जब इस विशाल जनसंख्या समूह को रोज़गार प्राप्त हो। अधिकांश कार्यशील जनसंख्या आज भी कृषि पर आश्रित है। इसे कृषि से उद्योग व सेवा क्षेत्र की तरफ मोड़ने के लिये आवश्यक है कि इन्हें संबंधित कौशल से युक्त किया जाए। चीन जैसा देश इसका अच्छा उदाहरण है।

3. भारत की गिनती 'जनांकिकीय लाभांश' (डेमोग्राफिक डिविडेंड) वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिये है, क्योंकि
   (a) यहाँ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है
   (b) यहाँ 15-64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है
   (c) यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है
   (d) यहाँ की कुल जनसंख्या अधिक है

उत्तर: (b)

व्याख्या: भारत की गिनती जनांकिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) वाले देश के रूप में इसलिये की जाती है क्योंकि यहाँ 15–64 वर्ष आयु वर्ग की कार्यशील जनसंख्या अधिक है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस कार्यशील जनसंख्या को 15–64 आयु वर्ग के रूप में निरूपित किया जाता है।

4. किसी भी देश के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी (सोशल कैपिटल) के भाग के रूप में समझा जाएगा?
   (a) जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात
   (b) इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक
   (c) कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप
   (d) समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर

उत्तर: (d)

व्याख्या: समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का जो स्तर है, उसे किसी भी देश के संदर्भ में, उस देश की सामाजिक पूंजी (Social Capital) के भाग के रूप में समझा जाता है।

- प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधनों का दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है। ये सामाजिक संसाधन 'पूंजी' के तीन रूपों में विभाजित किये जा सकते हैं: भौतिक संपत्ति एवं आय के रूप में 'आर्थिक पूंजी'; प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में 'सांस्कृतिक पूंजी' और सामाजिक संगतियों एवं संपर्कों के जाल के रूप में 'सामाजिक पूंजी'।
- पूंजी के ये तीनों रूप अक्सर आपस में घुले-मिले होते हैं तथा एक को दूसरे में बदला जा सकता है। उदाहरणतया, एक संपन्न परिवार का व्यक्ति अपनी आर्थिक पूंजी के ज़रिये महँगी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है; इस तरह वह अपनी आर्थिक पूंजी को सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वरूप दे सकता है। उसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति अपने प्रभावशाली मित्रों व संबंधियों (यानी अपनी सामाजिक पूंजी) के ज़रिये अच्छी सलाह, सिफारिश या जानकारी पा सकता है और इनके द्वारा एक अच्छी आय वाली नौकरी पाकर सामाजिक पूंजी को आर्थिक पूंजी में बदल सकता है।

5. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से असत्य है/हैं?
   1. जनसंख्या की गुणवत्ता देश की संवृद्धि दर निर्धारित करती है।
   2. निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है।

   कूट:
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

21

विविध
(Miscellaneous)

1. अमर्त्य सेन को उनके किस विषय-क्षेत्र में योगदान के लिये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था?
   (a) मौद्रिक अर्थशास्त्र (b) कल्याणकारी अर्थशास्त्र
   (c) पर्यावरणीय अर्थशास्त्र (d) विकासात्मक अर्थशास्त्र

उत्तर: (b)
व्याख्या: अर्थशास्त्र के लिये (1998 का) नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन पहले एशियाई हैं। शांति निकेतन (पश्चिम बंगाल) में जन्मे इस विद्वान अर्थशास्त्री ने लोककल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। इन्होंने कल्याण और विकास के विभिन्न पक्षों पर अनेक पुस्तकें तथा पर्चे लिखे हैं। ध्यातव्य है कि 1999 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से भी सम्मानित किया जा चुका है। अत: विकल्प (b) सही है।

2. निम्नलिखित में से कौन-से, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उद्देश्य हैं?
   1. ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार उपलब्ध कराना
   2. बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना
   3. लोगों में स्वावलंबन उत्पन्न करना और एक मज़बूत ग्राम-सामुदायिक भावना का निर्माण करना

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1 और 3

उत्तर: (a)
व्याख्या: भारत सरकार द्वारा 1957 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई। यह संगठन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है।
आयोग के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–
- रोज़गार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य।
- बिक्री योग्य वस्तुओं के उत्पादन करने का आर्थिक उद्देश्य तथा
- जनता में आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज या ग्राम-सामुदायिक भावना पैदा करने का व्यापक उद्देश्य।

3. 'घरेलू अंश आवश्यकता (डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट)' पद का संबंध किससे है?
   (a) हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से
   (b) हमारे देश में विदेशी टी.वी चैनलों को अनुज्ञप्ति प्रदान करने से
   (c) हमारे देश के खाद्य उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात करने से
   (d) विदेशी शिक्षा संस्थाओं को हमारे देश में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति देने से

उत्तर: (a)
व्याख्या: घरेलू अंश आवश्यकता (डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट) का संबंध भारत में सौर शक्ति उत्पादन के विकास से है। यह शब्द चर्चा में तब आया जब अमेरिका ने 2013 में WTO में भारत के ख़िलाफ़ यह शिकायत की कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के लिये भारत की सब्सिडी सौर घटक के विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं के ख़िलाफ भेदभाव करती है।

4. भारत सरकार की एक पहल 'SWAYAM' का लक्ष्य क्या है?
   (a) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना
   (b) युवा नव-प्रयासी (स्टार्टअप) उद्यमियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना
   (c) किशोरियों की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य का संवर्धन करना
   (d) नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा नि:शुल्क उपलब्ध कराना

उत्तर: (d)
व्याख्या: 'स्वयं' या 'स्टडी वेब ऑफ एक्टीव-लर्निंग फॉर यंग अस्पाइरिंग माइंड्स' योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत केंद्रीय वित्तपोषित संस्थाओं जैसे- आई.आई.टी., आई.आई.एम. एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपने विषय से संबंधित ऑनलाइन व्याख्यान देते हैं।
- इसके अंतर्गत कई सौ पाठ्यक्रम शामिल किये गए हैं। जैसे- वे सभी प्रकार के पाठ्यक्रम जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। अत: सीखने वाला व्यक्ति (लर्नर) किसी भी पाठ्यक्रम का ज्ञान या किसी भी प्रकार की शिक्षा इसके माध्यम से ग्रहण कर सकता है। यह जीवन भर सीखने का अवसर प्रदान कर आत्म-वास्तविकीकरण (Self-Actualisation) हेतु एक उपकरण साबित होगा।
- यहाँ सभी प्रकार के पाठ्यक्रम नि:शुल्क प्रदान किये जाएंगे परंतु सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले लर्नर को शुल्क अदा करना पड़ेगा।
- इसके प्रथम चरण में आई.आई.टी.-मुंबई, आई.आई.टी.-मद्रास, आई.आई.टी.-कानपुर, आई.आई.टी.-गुवाहाटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, जे.एन.यू., आई.आई.एम.-बंगलूरू इत्यादि अपने माध्यम से तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की सहायता से प्रौद्योगिकी क्षेत्र, सामाजिक विज्ञान, ऊर्जा, मैनेजमेंट, दैनिक विज्ञान इत्यादि में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आगामी 2-3 वर्षों में इस योजना के तहत कम-से-कम 1 करोड़ लोगों के लाभान्वित होने का अनुमान है।

5. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता 'आशा' (ASHA) के कार्य निम्नलिखित में से कौन-से हैं?

Think IAS

दृष्टि The Vision

Think Drishti

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

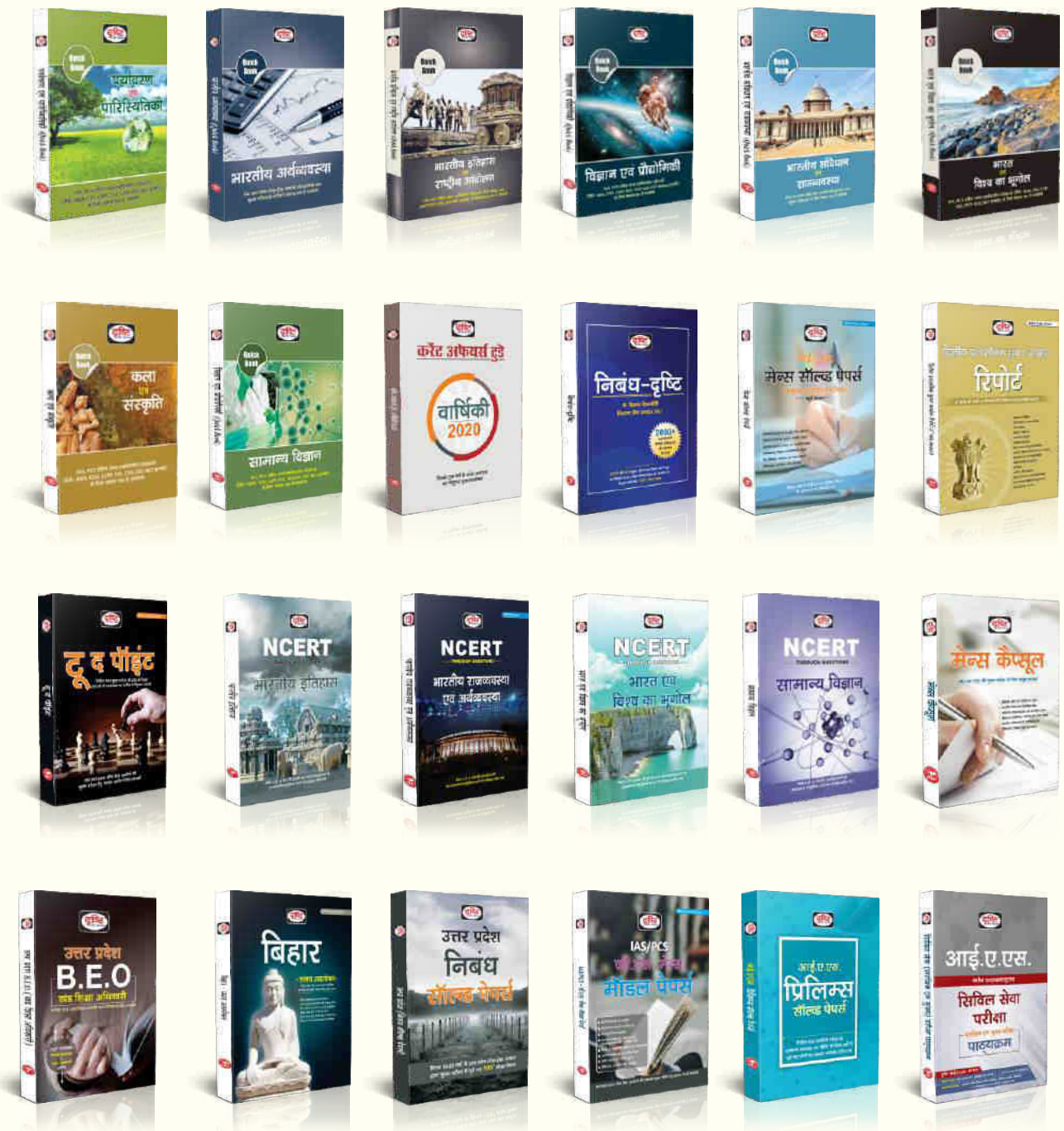

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485516, 87501-87501, 011-47532596

प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ की पुस्तकें

(यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पर केंद्रित)

1

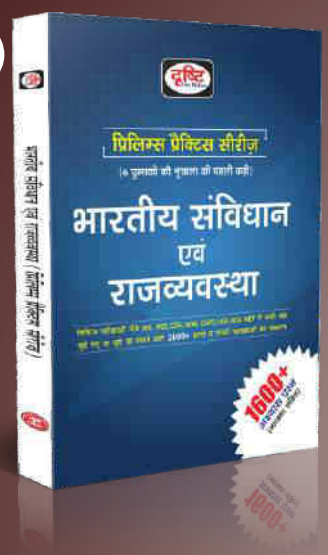

2

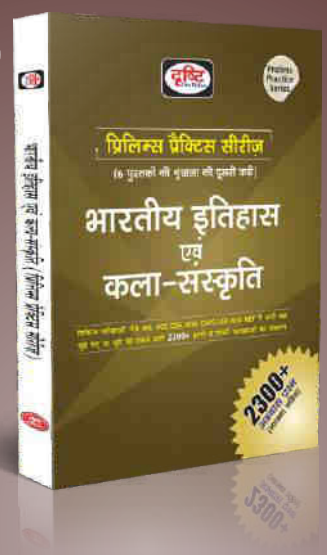

3

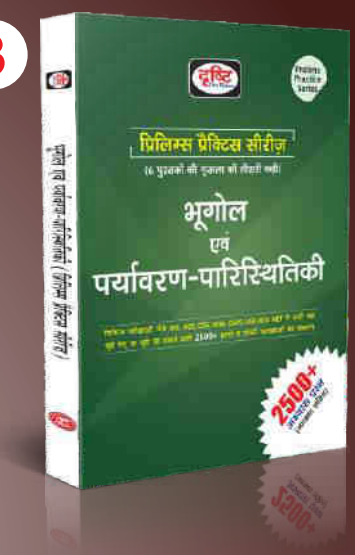

4

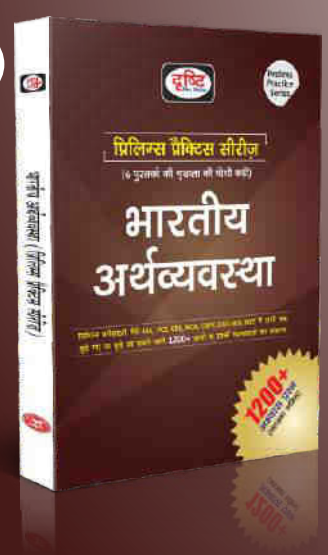

5

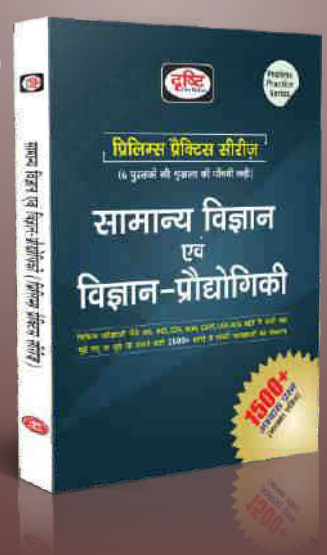

6

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

ISBN 978-81-945304-8-0

मूल्य : ₹ 240